लोक सम्पर्क विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन

www.chandigarh.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

चण्डीगढ़, 30 अगस्त - पंजाब के राज्यपाल और यूटी चण्डीगढ़ के प्रशासक श्री शिवराज वी. पाटिल ने चण्डीगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के अपग्रेडेशन के लिए केंद्र से उदारवादी रवैया अपनाने का अनुरोध किया है। श्री पाटिल आज नई दिल्ली में आयोजित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 11वीं कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री पाटिल ने कहा कि चण्डीगढ़ न केवल अपने शहरवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है बल्कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर रहा है। इससे हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009-2010 में चण्डीगढ़ के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 30 लाख से ज्यादा ओपीडीज थी। उन्होंने आगे बताया कि चण्डीगढ़ में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और कर्मचारियों पर बढ़ते दबाव के बावजूद स्वास्थ्य सूचकांकों ने गत वर्षो में काफ ी बेहतर नतीजे दिखाए हैं। श्री पाटिल ने कहा कि आईएमआर- 53, एमएमआर-254 और टीएफ आर-2.7 के राष्ट्रीय आंकड़ों के मुकाबले चण्डीगढ़ में आईएमआर- 28, एमएमआर-44 और टीएफआर-2.1 रहा है।

श्री पाटिल ने चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करने के लिए की गई विभिन्न पहलों का भी ब्यौरा दिया। इसमें स्कूल स्वास्थ्य योजना की मजबूती, योजना का मदरसों तक विस्तार, आंगनवाडियों की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, नशा-मुक्ति और उपचार

केंद्र की स्थापना व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्यान्वयन शामिल हैं।

श्री पाटिल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि चण्डीगढ़ प्रशासन केंद्रीय सरकार के सहयोग से मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है। इस वर्ष गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर-16 में नया ओपीडी ब्लॉक शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी नया ब्लॉक पूरा हो जाएगा। हालांकि निकटवर्ती राज्यों से बढ़ती रोगियों की संख्या से निपटने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कर्मचारियों, उपकरणों और भौतिक ढांचे संबंधी स्वास्थ्य आवश्यकताओं में बढ़ रहे अंतराल पर भी चिंता जताई।

पर्याप्त कर्मचारियों की मंजूरी की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री पाटिल ने कहा कि चण्डीगढ़ के विभिन्न अस्पतालों में कर्मचारियों, डॉक्टरों और नर्सो की भारी कमी है। हालांकि पिछले दशक के दौरान हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर भार बढ़ा है, किन्तु उससे निपटने के लिए कर्मचारियों की मंजूरी नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में पास काफी प्रस्ताव लंबित हैं। उन्होंने भारत सरकार से कर्मचारियों की मंजूरी संबंधी निम्नलिखित प्रस्तावों को तेज करने का अनुरोध किया-

- स्पेशलिटी ऑफ गैस्ट्रोएनट्रोलॉजी, वैस्क्यूलर थोरेसिक सर्जरी और यूरोलॉजी में 6 पदों के सृजन, रेडियोथैरेपी विभाग में 3 पद और जीएमसीएच-32 में जैनेटिक लैब और एनिस्थीसियोलॉजी विभाग में क्रमशः 6 और 19 पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव।
- जीएमसीएच में वरिष्ठ रेजिडेंटो के 13 पदों और नर्सो व तकनीकि कर्मचारियों के 657 पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव।

- गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर-16 में डॉक्टरों के 105 पदों और पैरा-मैडिकल कर्मचारियों के 553 पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव।

श्री पाटिल ने जोर देकर कहा कि सभी सेक्टरों विशेषकर दक्षिणी सेक्टरों में अतिरिक्त औषधालयों की स्थापना की आवश्यकता है। उन्होंने मौजूदा पीएचसी और सीएचसी के अपग्रेडेशन, गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर-16 में नये ब्लॉकों जैसे पैडिएट्रिक ब्लॉक, गाइनी ब्लॉक और प्रशासनिक ब्लॉक की स्थापना और दक्षिणी सेक्टरों में इसी हॉस्पिटल के समान एक अन्य हॉस्पिटल की स्थापना के लिए केंद्र से सहायता का अनुरोध किया।

श्री पाटिल ने जीएमसीएच-32 में 300 बैड से युक्त मल्टी स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर की स्थापना, जीएमसीएच-32 में सुविधाओं में इजाफा, 100 बैड से युक्त मैटरनीटी हॉस्पिटल की स्थापना, आयूष के लिए 30 बैड की आंतरिक सुविधा की स्थापना और कैंसर उपचार इकाई की स्थापना के लिए भारत सरकार से उदारवादी वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया।